श्री प्रमोद महाजन: सभापति जी, इस प्रश्न का इससे सीधे संबंध नहीं है लेकिन निकट भविष्य में भारत संचार निगम और महानगर टेलीफोन निगम का निजीकरण होने की कोई संभावना नहीं है।

SHRI V.V. RAGHAVAN: Mr. Chairman, Sir, our experience shows that private operators who enter into agreement with the Department of Telecom, do not fulfil their agreements. Though bank guarantees have been given, nothing is being done to recover the amount from defaulters. I would like to know from the hon. Minister what steps are being taken by the Government to ensure that these agreements are fulfilled by the private operators.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, private operators, in ILD sector, have been working since August, and they are making payments regularly. So, there is no question of private operators being defaulters, at this stage. As far as the VSNL is concerned, as I said, the agreement has been signed recently. We don't have any apprehension on VSNL, not paying money to us. At the same time, the Government has still 26 per cent of equity in that company. So, there is no question of VSNL being a defaulter, as far as BSNL or MTNL is concerned. If they become defaulters, we will take appropriate action, which is permissible under the law.

**326. [The questioner (Shri Harendra Singh Malik) was absent. For answer vide page 41.]*

राष्ट्रीय राजमार्ग - 83

*327. **श्री लालू प्रसाद:**
श्री विजय सिंह यादव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-83 के जहांनाबाद से डोभी तक के खंड की स्थिति अच्छी नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त खंड के संबंध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा उनके मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कार्रवाई करने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के जहांनाबाद-डोभी खंड की लंबाई 82 कि.मी. है। इसमें से लगभग 70 कि.मी. लंबाई सामान्यत: संतोषजनक स्थिति में है। इस खंड पर जहांनाबाद बाइपास के 48 से 50.5 कि.मी. तक 61.13 लाख रु. का एक आवधिक नवीकरण कार्य स्वीकृत किया गया है। रा. रा. 82 और 83 के खंड के सुधार के लिए 9.10 करोड़ रु. लागत की एक अन्य परियोजना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत रा. रा. 83 को 99 से 106 कि. मी. तक सुधारा जाएगा।

(ख) और (ग) जी हां। बोधगया-डोभी खंड के 107 से 125 कि. मी. में गुणता सुधार के लिए 494.29 लाख रु. का एक प्रस्ताव दिनांक 3.12.2002 को मंत्रालय में प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जा रही है। इसके बारे में जनवरी, 2003 के अंत तक निर्णय लिया जाएगा।

National Highway 83

†*327. SHRI LALU PRASAD:
SHRI VIJAY SINGH YADAV:††

Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Jahanabad to Dobhi section of National Highway No. 83 in Bihar is not in good condition;

(b) whether it is a fact that a proposal pertaining to the said section has been submitted to his Ministry by the State Government; and

(c) if so, whether Government propose to take any action in this regard and if so, by when?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (MAJOR GENERAL (RETD.) B.C. KHANDURI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of House.

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The original question was actually asked on the floor of the House by Shri Vijay Singh Yadav.

Statement

(a) The Jahanabad-Dobhi section of NH 83 is 82 km in length. Of this, about 70 km is in generally satisfactory condition. On this section, one work of periodical renewal from km 48 to 50.5 of Jahanabad bypass amounting to Rs. 61.13 lakh has been sanctioned. Another project for improvement of portion of NH 82 and NH 83 is being executed by CPWD at a cost of Rs. 9.10 crore. Under this project, km 99 to 106 of NH 83 will be improved.

(b) and (c) Yes Sir. A proposal amounting to Rs. 494.29 lakh for improvement of riding quality in km 107 to 125 of Bodhgaya-Dobhi section has been received in the Ministry on 3-12-2002 and is under examination. Decision will be taken by end January 2003.

श्री विजय सिंह यादव: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग के कितने प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्राप्त हुए हैं और कितने प्रस्ताव वापस कर दिए गए हैं? एन०एच० 83, जो कि बिहार की राजधानी पटना और बौद्धिक स्थल बोधगया को जोड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण एन०एच० है। इस पर सुधार का कार्य मात्र पंद्रह-बीस किलोमीटर का ही हुआ है। मुख्य कार्य जैसे चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण पुल-पुलियों का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। इससे यात्रियों का ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप क्वेश्चन पढ़ दीजिए, कह दीजिए कि क्यों नहीं किया गया है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: सभापति जी, एन०एच० 83 को जुलाई, 1999 में स्टेट हाई वे से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया था। इसके लिए यह कहना कि कोई काम नहीं हुआ है, पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। इस सड़क पर जो काम हुआ है, मैं उन्हें गिना दूंगा लेकिन उससे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि 1999 में जब इस सड़क को हमने प्रदेश से लिया था तब इस सड़क की हालत बहुत खराब थी। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के बाद हमने इस पर अभी तक करीब पंद्रह-सोलह करोड़ रुपया खर्च स्वीकृत किया है। आपने पूछा है कि क्या काम किया है, तो मेरे पास उसका विवरण है। जहांनाबाद बाई पास पर ढाई किलोमीटर रिपेयर के लिए हमने 61.13 लाख रुपए दिए हैं। एन०एच० 82 और 83, दोनों को मिलाकर एक योजना सी०पी०डब्ल्यू०डी० को दी गई है। इसके लिए 9.10 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। इस सड़क, एन०एच० 83 का, 99 किलोमीटर से 106 किलोमीटर तक का जो उसका हिस्सा है उस पर करीब चार करोड़ तक का खर्च आएगा। अभी तीन दिसम्बर को, बिहार से हमारे पास जो प्रस्ताव आया है, वह 494 लाख के करीब का

प्रस्ताव है। अभी इस पर विचार हो रहा है और इसे स्वीकृति दी जाएगी। इससे पहले हमने इसी सड़क, एन०एच० 83 पर आई०आई०क्यू०पी० एक किलोमीटर से दस किलोमीटर किया था। जिस पर 2.09 करोड़ का खर्च स्वीकृत किया है और अभी एक मोरहार पुल बन रहा है जिस पर 2.30 करोड़ का खर्च स्वीकृत है। इस प्रकार इस पर भी अभी तक चौदह-पंद्रह करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं।

श्री विजय सिंह यादव: सभापति जी, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि स्थिति संतोषजनक है लेकिन इसकी हालत बहुत जर्जर है। यह एक बौद्धिक तीर्थ स्थल है। यह रूट जापान के सहयोग से बना है। जापान सरकार ने यह रोड बनाया है। इन्होंने इसे 1999 से लिया है, लेकिन इसकी बहुत जर्जर हालत है। पटना से बोधगया तक 130 किलोमीटर की लंबाई है। इसका न कोई चौड़ीकरण हुआ है सिर्फ मरम्मत ही पंद्रह-बीस किलोमीटर तक की गई है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: माननीय सभापति जी, राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार की प्रक्रिया इस प्रकार है । हम पैसा प्रदेश सरकारों को देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसा बिहार को इस साल के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधारीकरण के लिए करीब 52 करोड़ रुपया दिया गया है। प्रदेश सरकारें हमको बताती हैं कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग से–जैसे इनके पास करीब 3300 किलोमीटर है–उसके कौन से हिस्से में कितने प्रकार का और किस प्रकार का सुधार किया जाए तथा कितना खर्च है, उसी के आधार पर देते हैं। तो यह प्रदेश सरकार हमको बताती हैं कि इस 52 करोड़ रुपए में से किस जगह कितना खर्च किया जाएगा। इसमें उन्होंने अभी तक हमको यही एक प्रस्ताव भेजा है जो 494 लाख का है। बाकी जितने प्रस्ताव आए हैं, बी०ओ०एस० के अन्तर्गत सब स्वीकृत कर दिए गए हैं।

श्री गया सिंह: मंत्री जी सब रोड्स में नहीं आते हैं। माननीय सदस्य ने जिसका सवाल उठाया है, मैं भी उसी रोड से जाता हूं। नालंदा हमारी बगल में है। वहां रोड की हालत बहुत खराब है। आप जो रुपए देते हैं क्या इसके लिए कोई मानीटरिंग कमेटी है? क्या इसकी जांच वगैरह भी होती है? यही मैं आपसे जानना चाहता हूं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: माननीय सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि हालत ठीक नहीं हैं। मेरे पास इस जगह का पूरा विवरण है। उनको ठीक जानकारी नहीं है। लेकिन मैं यह दुबारा दोहरा रहा हूं। जब राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाता है उस समय अगर यह स्टेट हाइवे की कैटेगरी का हो, उस स्टैंडर्ड का हो तब हमको खर्च कम लगता है। लेकिन उनकी पूरी जीर्ण-शीर्ण हालत से सुधार करने में समय लगता है। आपने मानीटरिंग के लिए कहा, तो हमारी तरफ से प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है, पीडब्ल्यूडी है उनको पैसा दिया जाता है और मानीटरिंग भी वे ही करते हैं। हम लोग अपनी तरफसे भी समय-समय पर जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन मेरे पास इस प्रकार

का आर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो वहां पर जाकर विस्तार से चेक करे। अगर कभी हमारे पास कोई शिकायत आती है तब हम यहां से टीम भेजते हैं। लेकिन मानीटरिंग की अधिकतर जिम्मेदारी प्रदेश सरकार पर है।

श्री सतीश प्रधान: सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा रास्तों के लिए दिया हुआ जो पैसा है क्या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको दूसरी जगह यूज किया है, क्या ऐसी मालूमात आपको है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: माननीय सभापति जी, एक प्रक्रिया है। प्रदेश सरकार से हमारे पास एक खास जगह के लिए धन मांगा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हम विस्तार से उनका प्रोजेक्ट और एस्टीमेट मांगते हैं और वह पैसा उसी के ऊपर खर्च होता है, दूसरी जगह वे खर्च नहीं कर सकते हैं।

श्री सतीश प्रधान: नहीं, ऐसा अनुभव हुआ है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर ऐसा पैसा दूसरी जगह यूज किया गया है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको ऐसी कुछ जानकारी है?

श्री सभापति: क्या आपकी जानकारी है? उनको तो बाद में पूछिएगा। क्या आपको जानकारी है या अनुमान से कह रहे हैं?

श्री सतीश प्रधान: अलग-अलग कमेटियों में काम करते समय मैंने यह अनुभव किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से गया हुआ पैसा उसी काम के लिए यूज में नहीं आता है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूड़ी: अगर आपके पास कोई जानकारी है तो इसके ऊपर उच्च स्तर के ऊपर जांच पड़ताल करवा देंगे। हमारी जानकारी में नहीं है।

**328. [The questioner (Shri Ram Jethmalani and Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan') were absent. For answer vide page 41 infra.]*

**329. [The questioner (Shri Amar Singh) was absent. For answer vide page 42.]*

Indo-Asean Summit on Economic Co-operation and Terrorism

*330. DR. T. SUBBARAMI REDDY:†
SHRI K. NATWAR SINGH:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the first-ever Indo-ASEAN Summit was held on 5th November, 2002 to focus on economic co-operation and terrorism;

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. T. Subbarami Reddy.